[श्री नाथू सिंह]

निकाला गया। लाखों रुपये हर वर्ष अकाल राहत कार्य के नाम पर वहां खर्च किये जाते हैं। यदि उस रुपये को योजना बना कर खर्च किया जाता तो आज तक उस समस्या का स्थायी समाधान हो गया होता। इस वर्ष भी पहले की भांति ही राजस्थान में अत्यधिक बाढ़ आयी है लेकिन इस बार एक विचित्र स्थिति राजस्थान की बन गई है। इस बार उन स्थानों पर भी, उन क्षेत्रों में भी बाढ़ आ गई जहां पहले लोग पानी के लिए तरसते थे। जो क्षेत्र, जो जिले हमेशा सूखे की स्थिति का सामना करते थे आज उन जिलों को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के लगभग 8 जिले तो इस बाढ़ से इतने अधिक प्रभावित हो चुके हैं कि वहां माल व जान की भारी हानि हुई है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं। हजारों मकान गिर गए। मवेशी मर गए। खेत डूब गए। फसल नष्ट हो गयी। गांव पानी में डूब गए। बांध टूट गए। नदियां उफन रही हैं। चार चार, पांच पांच फुट पानी भरा हुआ है। लोग पानी से घिर गए हैं। ऐसी स्थिति का सामना राजस्थान को पहले कभी नहीं करना पड़ा। 1924 के बाद सब से अधिक बाढ़ इस बार आई है। राज्य सरकार इस बारे में काफी चिन्तित है। कुछ कर भी रही है। लेकिन केवल यह पर्याप्त नहीं है। मैं स्वयं अपने क्षेत्र का दौरा कर के आया हूं। तहसील बेराठ, शाहपुरा, कोटपुतली, प्रागपुरा, पावटा, जमवा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। लगातार वर्षा के कारण खतरा घटने के बजाय बढ़ ही रहा है। अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं, प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे स्वयं इस विषय में रुचि ले कर राजस्थान को इस भयानक स्थिति में से उबारने के लिए विशेष सहायता केन्द्र से प्रदान करें। और युद्ध स्तर पर सहायता कार्य प्रारम्भ कराएं जिस से जन-धन की हानि होने से बचाया जा सके।

(iii) NEED FOR OLD AGE PENSION TO AGRICULTURAL LABOURERS AND LANDLESS POOR FARMERS

SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am raising under Rule 377 the following matter of urgent public importance for the consideration of the House.

India is basically a country of agriculture but millions of agricultural labourers have to earn their daily bread by doing inhuman labour till death. Though India is an agricultural country, members of the other communities, workers, Government employees and others in big establishments, apart from the poor farmers and agricultural labourers, enjoy privilege of pension and handsome monetary benefits like provident fund, gratuity, etc. at the old age which supports them at the fag end of their lives.

So far, both State and Central Governments have framed rules to help only the people belonging to the non-farmers group, resulting in the true owners of our agricultural country, the farmers, becoming neglected and deprived of all necessities of life. In every village thus numerous helpless overaged farmer brethern are struggling hard to survive in a very painful way till the last day of their lives decided by the Almighty. Sometimes they pass their days with half meal and sometimes they do not get it even. In order to rub off such serious disparity in our society and to usher in a new life to the agricultural labourers, the Central Government should frame a rule to implement the minimum old age pension, ncessary at the fag end of their lives, to agricultural farmers and labourers after 65 years of age. Otherwise we will not be able to stop the death of thousands of farmers and agricultural labourers due to starvation. The farmers and agricultural labourers of our country are placing this demand to the Janata Government through their elected representatives to eliminate such disparity.